

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 62/2017

अपीलार्थीगण—

बनाम

उत्तरदाता—

1. मूलाराम पुत्र जेठाराम
2. अशोक पुत्र जेठाराम
जाति माली निवासी भाडखा
तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.09.2017 जो प्रकरण सं. 122/2017 में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 05.02.2021

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 122/2017 सरकार बनाम मूलाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का भाडखा द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 565/181 रकबा 60-10 बीघा बारानी सोयम सरकारी भूमि में से 05-00 बीघा भूमि पर गैर सायलान मूलाराम, अशोक पि0 जेठाराम कौम माली साकिन भाडखा द्वारा बाजरी व ग्वार बोझा व अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी ने अपने बयानों में यह भी उल्लेखित

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया कि अतिक्रमी बार-बार समझाईस के उपरांत पुनः अतिक्रमण किया है, गत वर्ष मु.न. 113/16 दर्ज कर निर्णय दिनांक 19.10.2016 की पालना में बेदखल किया गया था, अतः आदतन अतिक्रमी है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं बयान पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल द्वारा अवैध कब्जा करना स्वीकार किया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(2) के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 22.09.2017 के द्वारा 13.00/- रुपये जुर्माना अधिरोपित करने के साथ-साथ एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने एवं विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाट्स ने दिनांक 25.10.2017 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलाट्स की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलाट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। अपीलाट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलाट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं सिविल कारावास का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान




जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट्स की ओर से यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स की तलबी हेतु जारी नोटिस स्वयं अपीलांट्स से तामील होना कथन किया है जबकि अपीलांट संख्या 2 का नोटिस तामील नहीं है न ही अपीलांट संख्या 2 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष हाजिर हुआ। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 22.09.2017 को ही अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था जिससे यह स्पष्ट हों कि अपीलांटगण का विवादित आराजी पर कब्जा है। केवल मात्र हलका पटवारी रिपोर्ट व मौखिक कथनों के आधार पर अपीलांटगण को दण्डित नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा जल्दबाजी में किया गया कार्य न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2003 आरआरडी 504 श्रीमती चन्दा बनाम राजस्थान राज्य में यह निर्धारित किया है कि "Justice hurried is Justice burried." इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

6. रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलांट्स के विरुद्ध हलका पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट्स द्वारा ग्राम भाड़खा के खसरा नम्बर 565/181 रकबा 60-10 बीघा बारानी सोयम सरकारी भूमि में से 05-00 बीघा भूमि पर गैर सायलान मूलाराम, अशोक पि0 जेठाराम कौम माली साकिन भाड़खा द्वारा बाजरी व ग्वार बोकर कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट्स



जिला कलेक्टर
बाड़मेर

सं. 1 मूलाराम उपस्थित हुआ तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया हैं जिसके लिये तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन प्रकरण सं. 122/2017 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2017 के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया गया था। अपीलाट्स द्वारा इसी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा-काश्त करने पर अपीलाट्स पर जुर्माना अधिरोपित करने के साथ ही एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथा अपीलाट्स की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. हमने अपीलाट्स के अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाट्स ने इस अपील के द्वारा खसरा नम्बर 565/181 की भूमि पर कब्जा नहीं होने का कोई अभिकथन नहीं किया गया है और न ही पूर्व में उसके विरुद्ध संस्थित कार्यवाही एवं बेदखली आदेश को अस्वीकार किया है। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलाट्स की जानकारी में आने पर अपीलाट सं. 1 मूलाराम स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तथा मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण स्वीकार किया गया। यदि उसे अपना जवाब प्रस्तुत करना था तो लिखित में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अवसर मांग सकता था। इसी मुतनाता भूमि पर अपीलाट्स द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में भी अवैध रूप से काश्त कर कब्जा किया था जिस पर उसके विरुद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर, सुनवाई उपरांत अपीलाट्स को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश दिनांक 19.10.2016 पारित किया गया एवं इस आदेश की पालना में मौके से बेदखल किया गया। इसके बावजूद भी अपीलाट्स द्वारा पश्चातवर्ती वर्ष में भी अतिक्रमण किया गया हैं जिसके



जिला कलेक्टर
बाड़मेर

संबंध में प्रकट किया कि अपीलांट्स भूमिहीन हैं एवं इस भूमि पर लम्बे समय के काबिज होने से प्रकरण नियमन योग्य है किन्तु अपीलांट्स द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष इस संबंध में साक्ष्य दस्तावेजों सहित कोई अभिकथन किया गया है। विवादित भूमि सरकारी है जिस पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत अपीलांट्स द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिये एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2017 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. आदेश आज दिनांक 05.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर